AIDWA

सितम्बर, 2022

न्यूज़ लैटर

1. संपादकीय

2. बिलकिस बानो केस (क्या ये न्याय का अंत है?)

- सुभाषिनी अली
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एडवा

3. अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हि0प्र0 का 12वां राज्य सम्मेलन 2-3 जुलाई, 2022 को मण्डी में सम्पन्न

- मंजीत राठी
केंद्रीय कमिटी सदस्य, एडवा

4. गैर-बराबरी सभी के लिए घातक है

5. एडवा उत्तराखण्ड राज्य का, 7वा राज्य सम्मेलन संपन्न

- सनुीता पाण्डे
केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा

6. गंगा जमुनी तहज़ीब को बचाने तथा सद्भाव व एकजुटता बनाए रखने के लिए .. भाईचारा सम्मेलन

- मधु गर्ग
केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा

सम्पादकीय

सुभाषिनी अली
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एडवा)

अपने हर बुलेटिन में महिलाओं पर बढती हिंसा, बढती साम्प्रदायिकता, संविधान पर नए हमले जैसी ख़बरों को हमे छापना पड़ता है. कहीं कहीं कुछ आशा की किरणे दिख जाती हैं जिनकी सूचना आपको देना हम आवश्यक समझते हैं. तो चलिए, एक ऐसी आशानिवित करने वाली खबर से इस सम्पादकीय को शुरू करते हैं.

अगस्त महीने की शुरुआत में ही इस बात की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी की बिहार में राजनैतिक भूचाल हो सकता है. दरअसल, महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा शिव सेना को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चलने वाली धर्मनिरपेक्ष दलों की मिली-जुली सरकार को पलट दिया गया और भाजपा द्वारा नियंत्रित शिव सेना के बागी शिंदे के नेतृत्व में सरकार बन गयी. इससे धर्मनिरपेक्ष ताकतों और महाराष्ट्र की जनता को ज़बरदस्त झटका लगा. इस घटना ने बिहार में NDA की सरकार का नेतृत्व करने वाले नितीश कुमार को आगाह कर दिया की इसी तरह का खेल उनके साथ भी भाजपा कर सकती है और उन्होंने तेज़ी के साथ पैंतरा बदला और राजद के साथ समझौता कर उसके साथ साझा सरकार बनाने का काम किया. बहुत दिन के बाद, भाजपा के षड्यंत्रकारी गतिविधियों की करारी हार हुई और उनको मुंह की खानी पड़ी. हिंदी भाषी एक बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में भाजपा के सहयोग से चलने वाली सरकार का हटना और उसकी जगह धर्म-निरपेक्ष दलों की सरकार का बनना एक महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना है और निश्चित तौर पर इसने भाजपा से पीड़ित लोगों को काफी राहत दिलवाने का काम किया.

इसके आलावा, लेकिन, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियाँ ही घटी हैं. इनमे सबसे अधिक निंदनीय, खतरनाक और भाजपा के घिनौने चेहरे का पूरी तरह से पर्दाफाश करने वाली घटना थी बिलकीस बानो के मामले में ११ सजायाफ्ता बलात्कारी-हत्यारों का गुजरात सरकार द्वारा छोड़ा जाना. इस मामले की पूरी रिपोर्ट इस बुलेटिन में है लेकिन गुजरात सरकार का यह कदम और इस पर प्रधान मंत्री की चुप्पी एक बार फिर हमे इस बात की याद दिलाती है की न्याय की प्रक्रिया को किस हद तक तोड़-मरोड़कर अन्याय को सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया गया है.

बड़ी ख़बरों के पीछे, कितनी असंख्य अत्याचार की कहानियां छिप जाती हैं, इसकी याद एक बार फिर आई जब आपके सम्पादक ने ३१ तारीख को खरगौन में दंगा-पीड़ितों से मुलाक़ात की. खरगौन मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां भाजपा ने अपनी खोई हुई सीटों पर फिर से कब्ज़ा जमाने के लिए साम्प्रदायिक तनाव और हिस्सा का सहारा लिया है. तमाम लोगों ने कुख्यात कपिल मिश्र का नाम सुना है. यह वहीं शख्स है जिसने दिल्ली में नफरत फैलाने के इरादे से गंदे भाषण दिए और घटिया नारे लगाए. पूर्वोत्तर दिल्ली में २०१९ में दंगा भड़काने में उनका बड़ा हाथ था. यही कपिल मिश्र दिल्ली से बहुत दूर, रामनवमी के त्यौहार के समय, खरगौन पहुंचे. यहाँ हर साल, रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसका स्वागत स्थानीय मुसलमान करते हैं, हार-मालाओं से जुलूस में भाग लेने वालों का अभिनंदन करते हैं. इस साल, जुलुस आया, मुसलमानों के मोहल्ले में रुका और फिर आगे नहीं बढा. वहीं खड़ा रहा. DJ बजाय गया, अश्लील नारे लगाए गए और जब नमाज़ पढने के बाद लोग मस्जिद से निकले तो उन पर हमला कर दिया गया. पुलिस देखती ही रही. लोगों के दुकान और मकान जलाए गए और २०० से अधिक मुसलमान जिनमे नाबलिग लड़के भी थे गिरफ्तार कर लिए गए. वे अभी भी बंद हैं. यह रमजान का महीना था. लोगों की ईद बहुत ही कडवी बना दी गयी.

CPIM का प्रतिनिधि मंडल हादसे के तुरंत बाद खरगौन गया. और कोई वहां लोगों की सुद्ध लेने नहीं गया. हमने कुछ राहत की सामग्री भी पहुंचाई और पूरे मामले की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया.

३१ को मैं cpim के नेताओं के साथ खरगौन गयी. बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित लोग हमसे मिले. उनमे औरते ही अधिक थी. उनके घर के पुरुष ५ महीनो से जेल में थे. कुछ पता नहीं चल रहा है की उनका क्या होगा. यह परिवार गरीब, मजदूरी करने वाले लोगों के हैं. बच्चों का पेट भरा नहीं जा रहा है तो पढ़ाई तो छूट ही गयी है. पूरी तरह से निराश हैं यह लोग. कोई भी उनकी सुनने और कहने वाला नहीं है.

हम लोगों ने उन्हें इतना ही भरोसा दिलाया की हम उनके साथ खड़े रहेंगे और जो कुछ भी उनकी मदद में कर सकते हैं वह करेंगे.

खरगौन की कहानी देश के कोने-कोने में दोहराई जा रही है. सांप्रदायिक विभजन और ध्रुवीकरण का सहारा लेकर हमारे तमाम अधिकारों पर सरकार कुठाराघात कर रही है. इन कहानियों को धीरज से सुनना और इनको सुनाना हमारा बड़ा काम बन गया है. लोगों को

जताना और जगाना और फिर उन्हें अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लामबंद करना हमारी प्राथमिकता बन गई है.

सम्पादकीय समाप्त करते-करते, एक आशा की किरण और नज़र आई है: हमारे बहन, हमारी साथी, हमारी सहयोगी तीस्ता सेतालवाद को सर्वोच्च न्यायलय ने ज़मानत पर छोड़ने का फैसला सुनाया है.

संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा! लड़ाई हमारी जारी रहेगी!

बिलकिस बानो केस
क्या ये न्याय का अंत है?

सुभाषिनी अली
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एडवा)

भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल के अमृत महोत्सव समारोह को गहरी ठेस लगी जब गुजरात सरकार द्वारा उस दिन 11 लोगों को जिन्हें 2002 में राज्य में मुसलमानों के भीषण नरसंहार के दौरान उनके द्वारा किए गए कई बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था चौंकाने वाली छूट दी गई । जब इस छूट की खबर सार्वजनिक हुई, तो अपराधों की एकमात्र उत्तरजीवी बिलकिस बानो केवल इतना ही कह पायीं कि 'क्या यह न्याय का अंत है'।

यादें एक बार फिर सताती हैं

मैं वृंदा करात, किरण मोघे, मरियम धवले, सुबोध रॉय और अरुण मेहता सीपीआई (एम)-एडवा प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिसने 10-12 मार्च, 2002 गुजरात का दौरा किया था। छूट के इस आदेश ने 20 साल पुरानी यादें ताजा कर दीं। नए सिरे से हमें परेशान करने के लिए ।

इस दौरे में हम गोधरा स्टेशन गए थे, फिर हम इकबाल प्राइमरी स्कूल कैंप गए जहाँ हमारी मुलाकात बिलकिस बानो से हुई। यह उनके साथ हमारी मुलाकात की रिपोर्ट के कुछ हिस्से : "रंधिकपुर (जिला दाहोद) गांव की लगभग 21 साल की एक युवती बिलकिस बानो w/o याकूब पटेल है, जो वर्तमान में इक़बाल प्राइमरी स्कूल कैंप, गोधरा में रह रही है। उसने हमें बताया कि उसके गांव के सभी मुस्लिम घरों पर ग्रामीणों और बाहरी लोगों ने हमला किया और वह अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ भागने में सफल रही। उनके साथ उनकी मां, उनकी 3 साल की बच्ची, सालिहा, उनकी बहनें, मुमताज और मुन्नी, उनके भाई, इरफान और असलम, उनके मामा, मजीद, दो अन्य पिता की बहनें, सुगरा और अमीना, उनमें से एक के पति, यूसुफ, अमीना का बेटा, और तीन बेटियां, शमीम, मुमताज और मदीना और शमीम का बेटा हुसैन। बिलकिस पांच महीने की गर्भवती है और बहन शमीम"।

बिलकिस के साथ तीन लोगों ने रेप किया था। उनका कहना है कि अन्य युवतियों के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बच्चे को उससे छीन लिया गया और मार डाला गया और फिर उन सभी पर हमला किया गया। उसे उसके परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था, जो नवजात शिशु सहित सभी मारे गए थे। वे पत्थर से ढके हुए थे। वह पूरी रात वहीं पड़ी रही । गोधरा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। उसने उन लोगों का नाम लिया है जिन्होंने उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की और उसके साथ बलात्कार करने वालों का नाम लिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने इस तथ्य की पुष्टि की कि उसकी जांच

की गई थी और उन्हें संभोग और चोटों के सबूत मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अभी तक फोरेंसिक जांच के लिए सबूत नहीं लिए हैं।

यह बिलकिस की न्याय की लंबी और साहसी खोज की शुरुआत थी जिसमें उन्हें गुजरात पुलिस और प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से उस समय की मोदी सरकार के इशारे पर हर मोड़ पर नाकाम कर दिया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि बिलकिस का बयान दर्ज किया गया था और एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके मेडिकल परीक्षण से बलात्कार के आरोप की पुष्टि हुई थी, गुजरात पुलिस ने इस आधार पर मामला बंद कर दिया कि उसके बयान में कुछ विसंगतियां थीं। एनएचआरसी के हस्तक्षेप ने मामले को जिंदा रखा लेकिन, इस मामले में न्याय के पहिये बेहद धीमी गति से चल रहे थे। अंत में, इसे महाराष्ट्र की सीबीआई अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया और 2008 में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बिलकिस को मुआवजा दिया गया और गुजरात सरकार से उन्हें सरकारी रोजगार और एक घर मुहैया कराने को कहा गया। उन्हें मुआवजा पाने के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जबकि नौकरी और घर पहुंच से बाहर रहे।

कटे पर नमक

उसके शरीर और ज़हन पर घाव असहनीय रूप से गहरे रहे होंगे। शायद यह सोचा था कि उसने न्याय का एक टुकड़ा जीत लिया है और शायद समय बीतने के साथ कुछ ठीक हो गया। दुख की बात है कि उनके परिवार के सदस्यों और खुद के खिलाफ किए गए अकथ्य क्रूरता के कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को छूट दिए जाने की खबर, जिसमें एक दिन के बच्चे और तीन साल के बच्चे की हत्या शामिल थी, उन सारे ज़ख्मों को फिर से खोला और उन पर नमक डाला। दंग रह गई, वह केवल इतना कह सकी कि 'क्या यह न्याय का अंत है?'

जबकि इन 11 दोषियों की रिहाई अपने आप में भयावह थी, मनुवादी-हिंदुत्व ब्रिगेड के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं अप्रिय और अशुभ थीं। महिलाओं सहित उनमें से कई ने अपराधियों को माला और मिठाई के साथ जेल से बाहर आने पर बधाई दी और एक भाजपा विधायक, गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य, ने कहा कि अपराधी ब्राह्मण और संस्कारी थे।

इन दो प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि न्याय की प्रक्रिया का पूरी तरह से विकृत होने का खतरा है। संविधान और कानून का शासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि समान अपराध करने वाले सभी दोषियों को समान सजा दी जाए और अपराधों के पीड़ितों को समान न्याय मिले। इन अपराधियों को जो छूट दी गई है और उनके समर्थकों की प्रतिक्रियाएं

यह संकेत दे रही हैं कि अपराधियों को अब उनकी जाति और समुदाय के अनुसार दंडित किया जाएगा, और उनके पीड़ितों की जाति और समुदाय को ध्यान में रखा जाएगा ।

जाति, जो मायने रखती है

यह बेहद परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। यदि इसका विरोध नहीं किया जाता है और जी जां से से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, तो यह सभी नागरिकों की समानता और सभी नागरिकों के लिए समान न्याय के संवैधानिक प्रावधानों के स्थान पर होगी एक मनुवादी प्रणाली जो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है और न्याय-वितरण की पूरी तरह से असमान प्रणाली भी है।

यह तथ्य कि गुजरात की भाजपा सरकार इन 11 घिनौने अपराधियों को छूट देने पर तुली हुई है और प्रधान मंत्री और गृह मंत्री उनकी चुप्पी से अपनी सहमति प्रदर्शित कर रहे हैं, यह एक अशुभ संकेत है कि न्याय की तबाही उनके एजेंडे का हिस्सा है । उन्होंने गुजरात में एक बहुत मजबूत संकेत दिया है कि जो बहुसंख्यक समुदाय के हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा के भयानक, बर्बर कृत्यों को अंजाम देते हैं, उन्हें नायकों के रूप में लाया जाना चाहिए। हाथरस में भी यही हुआ - यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने वहाँ भी एक कड़ा संदेश दिया कि उच्च जाति के बलात्कारियों और हत्यारों, जिनकी पीड़ित एक दलित महिला है, को भी राज्य द्वारा सुरक्षा और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

इसका यथासंभव व्यापक विरोध किया जाना चाहिए। यह बहुत ही स्वागत योग्य है कि गुजरात में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया है और देश के अधिकांश हिस्सों में आक्रोश जारी है। सेवानिवृत्त सिविल सेवक भी इसकी निंदा में मुखर रहे हैं। दोषियों को मिली छूट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और उस पर सुनवाई हुई है ।

जनहित याचिका में, एडवा की उपाध्यक्ष के रूप में मैं, साथ में कार्यकर्ता रेवती लाल और पूर्व वीसी, लखनऊ विश्वविद्यालय, रूपरेखा वर्मा याचिकाकर्ता हैं । यह याचिका कई मुद्दों पर गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देती है। पहला यह कि छूट देने का फैसला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति साल्वी, जिन्होंने अभियुक्त के खिलाफ फैसला सुनाया, से परामर्श किए बिना तय किया गया था। उनका कहना है कि वह इस छूट के पूरी तरह से खिलाफ हैं। दूसरे, गुजरात सरकार ने भी यह कदम उठाने से पहले केंद्र सरकार से सलाह नहीं ली थी।

जनहित याचिका में अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराधों का विवरण दिया गया है और यह भी कहा गया है कि एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्न उठाए थे जिनके आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार किया जा सकता है ।

- क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किए बिना अपराधी का एक व्यक्तिगत कृत्य है;
- क्या इस दोषी को अब और कैद करने का कोई सार्थक उद्देश्य है;
- क्या भविष्य में अपराध करने की कोई संभावना है;
- क्या अपराधी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है;
- दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

याचिका पर तत्कालीन सीजेआई (CJI) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने कार्यालय के अंतिम दिन, 25 अगस्त को सुनवाई की थी। अन्य दो न्यायाधीश गुजरात सरकार की याचिका से सहमत थे कि गुजरात सरकार ऐसा आवेदन स्वीकार करने में सक्षम थी। 11 दोषियों द्वारा छूट के अनुरोध को सुनने के लिए (पहले गुजरात के एचसी (HC) ने फैसला सुनाया था कि याचिका को बॉम्बे एचसी (HC) द्वारा सुना जाना चाहिए क्योंकि सजा वहां हुई थी)। इसलिए, यह एक तनावपूर्ण सुनवाई थी जिसमें दो न्यायाधीशों में से एक ने अपने फैसले का जोरदार बचाव किया। हालाँकि, CJI ने हस्तक्षेप किया और हमारी जनहित याचिका में उठाई गई आपत्तियों और सवालों के जवाब के लिए गुजरात सरकार को नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि इस पर दो हफ्ते के भीतर सुनवाई होगी ।

जहां तक अदालत में न्याय की लड़ाई का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दरवाजा खुला रखा है। हालाँकि, यह लड़ाई केवल कानूनी लड़ाई तक ही सीमित नहीं रह सकती । इसे पूरे देश के लोगों द्वारा लड़ा जाना चाहिए, वे लोग जो कानून के शासन, संविधान और मानवता के संरक्षण के लिए चिंतित हैं। यह अब बिलकिस की लड़ाई नहीं, हमारी है। यह लड़ाई हमें जीतनी होगी।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हि0प्र0
का 12वां राज्य सम्मेलन
2-3 जुलाई, 2022 को मण्डी में सम्पन्न

मंजीत राठी
केंद्रीय कमिटी सदस्य

जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश राज्य का दो दिवसीय राज्य सम्मेलन 2-3 जुलाई को मण्डी के तारा चन्द भवन में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की शुरूआत 2 जुलाई,2022 को ध्वजारोहण से हुई। ध्वजारोहण राज्य अध्यक्षा डॉ0 रीना सिंह ने किया। इसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद राज्य सचिव फालमा चौहान ने सबका स्वागत किया और सम्मेलन को संचालित करने के लिए अध्यक्ष मण्डल, मिनटस कमेटी, क्रेडिशियल कमेटी और सटीयरिंग कमेटी का प्रस्ताव रखा और सदन द्वारा इसका अनुमोदन करने के बाद राज्य अध्यक्ष द्वारा शोक प्रस्ताव रखा गया और दो मिनट के लिए मौन भी रखा गया। इसके बाद स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री डीपी गुप्ता जो डीवाईएफआई के अध्यक्ष भी रहे हैं उन्होंने अपना स्वागत भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने जनवादी महिला समिति के आंदोलन के सामने आ रही चुनौतियों को बहादुरी से सामना करने का संदेश भी दिया।

उद्घाटन सत्र

सम्मेलन का उदघाटन राष्ट्रीय महासचिव मरियम धवले ने किया जिन्होंने अपने भाषण में कहा मुल्क के अंदर जो भी घटनाऐं घटती है उसका असर महिलाओं के उपर पड़ता है उसके लिए जनवादी महिला समिति संघर्ष करती है कोरोना काल में 10 प्रतिशत लोगों के उपर कोई फर्क नहीं पड़ा है लेकिन 80 से 90 प्रतिशत लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। लोगों को लॉकडाउन और कफर्यू जैसे शब्दों का पता भी नहीं था। जो लोग रोज काम करते थे वह बर्वाद हो गए। उन्होंने यह भी कहा करोना महामारी तो पूरे विश्व में आई लेकिन ज्यादा मोंते अमेरिका, ब्राजील तथा भारत में हुई है। अपने देश के लोगों के लिए सभी सरकारों ने पहल कदमी की लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार ने पहलकदमी ही नहीं की। स्पेन की सरकार ने नीजि दवाखाना तक अपने अधीन ले लिए थे और उनका सरकारी करण किया गया। भारत में हमारी मांग थी की गैर आयकर दाता के खाते में 7500 रूपये डाले जायें परन्तु सरकार ने हमारी नहीं सुनी।

वैक्सीन लेना हमारा अधिकार है और सरकार का काम वैक्सीन देना है आज भी टीका बाजार में बिक रहा है हमारे देश को उस दृश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए जिस दृश्य में किसी

औरत का भाई, पति और किसी का बेटा मर गया हो उसका अन्तिम संस्कार करने के लिए उसकी जेब में पैसे तक नहीं थे। शवों को गंगा में बहा दिया गया। इतनी बेरहम सरकार को यह देश कभी माफ नहीं कर सकता।

नई शिक्षा नीति लाकर गरीबों के बच्चों को बर्वाद कर दिया है आज दूनिया में भारत स्वास्थ्य के उपर कम खर्चा करने वाला देश है। इस देश में कोरोना काल में 4 करोड़ लोगों के राशन

कार्ड रद्द कर दिये गए इस महामारी के दौर में तीन चीजें सबसे अधिक बढ़ गई थी। जिसमें परिवारिक हिंसा, कम उम्र में लड़कियों की शादी तथा औरतों का देह व्यापार, उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि धर्म सबका व्यक्तिगत मामला होता है इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाल सकते है लेकिन अगर धर्म और जाति की बात आए तो आपस में लड़ाई लड़ते है। इस देश की सरकार हिन्दू मूस्लमान में दंगों को कराकर लोगों को गुमराह करते हैं। मोदी ने 7 साल में अदानी और अम्बानी को 10.72 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। दवाई मंहगी, तेल महंगा, डीजल, पैट्रोल महंगा हो गया है आर्मी नेवी, खत्म कर दिया है। इसको ठेके पर कर दिया है उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न विभागों में जैसे एलआईसी, रेलवे, स्कूल आदि में लाखों पद खाली पड़े हैं। उन्होनें कहा कि भाजपा आरएसएस ने संविधान को ही नहीं माना है वह इस देश में मनुस्मृति को लाने की कोशिश कर रहे है। ताकि कभी इस देश में गरीब का बच्चा कभी डाक्टर न बन सके। आज भारत जलती हुई आग पर खड़ा है लेकिन हम इसे खत्म करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं।

सम्मान समारोह:-

स्वागत भाषण के बाद जनवादी महिला समिति ने विभिन्न तरह की हिंसा का बहादूरी से सामना करने वाली महिलाओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें हिमाचल प्रदेश में जनवादी महिला समिति के महिला हिंसा के प्रति संघर्ष नजर आ रहे थे। इन चारों महिलाओं में सबसे पहले ममता नेगी जो कि कुल्लू जिला से सम्बन्ध रखती है वर्तमान में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बतौर जनवादी महिला समिति में काम कर रही है उन्होंने अपने साथ हुई हिंसा और उस हिंसा का डटकर विरोध किया फिर भी हार नहीं मानी उन्हें उस बहादूरी के लिए जनवादी महिला समिति ने सम्मानित भी किया। दूसरी महिला सुषमा जिन्होंने अपने पंचायत में पीने के पानी के लिए संघर्ष किया था जिसमें उनको होटल मालिक जिनके पानी के कनैक्शन जो अवैध थे उनको पकड़ा गया उसके खिलाफ बहादुरी से कार्य किया थ। तीसरी युवती सावित्री थी सावित्री दलित परिवार से संबंध रखती है पिछले वर्ष दिसम्बर के महीने में सावित्री जब कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में उसे स्वर्ण जाति के एक लड़के ने धक्का मारा वह 500 मीटर नीचे पहूंची उसे पूरे शरीर में चोटे आई थी और उसके

हाथ पांव फ्रैक्चर हो गये था। परिवार वालों ने सब कुछ करने के बाद जनवादी महिला समिति के पास आई तो फिर हमारा एक प्रतिनिधी मण्डल शिमला के एएसपी से मिला हमारा दबाव डालने के बाद फिर उस केस में एट्रोसीटी लगवाई गई और केस आगे बढ़ गया। अन्त में उस युवा को पूलिस ने गिरफ्तार किया और उसे 15 दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया। अभी केस चल रहा है इसकी बहादूरी को भी जनवादी महिला समिति ने सम्मानित किया। चौथी महिला सिरमौर से मीरा चौहान जिन्होंने शराब के ठेके को लेकर अपनी लड़ाई लड़ी थी।

विरादराना संगठनों के शुभकांमना संदेश:-

विरादराना संगठनों के नेताओं ने अपने शुभकामना संदेश भी दिए संदेश देने वालों में किसान सभा से कुशाल भारद्वाज, सीटू से भूपेन्द्र सिंह, दलित शोषण मुक्ति मंच से रविकांत, एसएफआई से अमित ठाकुर तथा नौजवान सभा से सुरेश सरवाल और हिमाचल प्रदेश मैड़िक्ल रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन से साथी जगदीश तथा जन विज्ञान मोर्चे से भीम सिंह ने सम्मेलन को अपने शुभकामना संदेश दिए और सभी साथियों ने सांझी गतिविधियों के उपर बल दिया।

राज्य सचिव की रिपोर्ट:-

राज्य सचिव द्वारा पिछले तीन वर्ष की रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट पर सभी जिलों द्वारा ग्रुप में चर्चा की गई और फिर रिपोर्ट पर चर्चा के लिए 16 प्रतिनिधियों ने इसकी चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा से यह जाहिर हो रहा था कि कोविड़ काल में संगठन का काम काज काफी प्रभावित हुआ है सभी प्रतिनिधियों ने अपनी चर्चा को संगठन पर ज्यादा केन्द्रित किया थ। संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कमेटियों को सक्रिय करना तथा उनका प्रशिक्षण शिविर लगाना, स्थानीय ईकाईयों को मज़बूत करना तथा संघर्ष के लिए स्थानीय मुद्दों को चिन्हित करना राज्य केन्द्र को और सुदृढ़ करना आदि इन सब कामों पर तथा सदस्यता पर भी चर्चा की गई। सब प्रतिनिधियों में संगठन के प्रति लगाव दिख रहा था और आने वाले तीन वर्षों के लिए सभी ने अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए संगठन को मज़बूत करने का आश्वासन दिया।

राज्य प्रभारी का भाषण:-

रिपोर्ट पर चर्चा के सवालों का जबाव राज्य सचिव द्वारा दिया गया तथा राज्य प्रभारी मनजीत राठी ने भी अपना पर्यवेक्षक भाषण रखा और उन्होंने प्रतिनिधियों के प्रश्नों के साथ साथ जनवाद, समानता और नारी मुक्ति पर भी अपने विचार रखे और उन्होंने यह भी कहा

कि हिमाचल के इस राज्य सम्मेलन में विभिन्नता में एकता की झलक देखने को मिल रही है। गरीबी, महंगाई, भूखमरी का सबसे बड़ा मुद्दा है एक तरफ तो संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे परन्तु इसके बावजूद भी कोरोना काल में यह सब देखने को मिला। स्वयं सहायता समूहों में ब्याज दर 4 प्रतिशत से उपर नहीं होनी चाहिए यह भी उन्होंने रेखांकित किया।

सम्मेलन में महिला हिंसा, मनरेगा, बढ़ती महंगाई, अग्निपथ योजना के खिलाफ तथा नशे के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किये गये।

सम्मेलन में राज्य उपाध्यक्ष विना वैद्य द्वारा वित्त की रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें उन्होंने पिछले तीन वर्ष का पूरा लेखा जोखा सम्मेलन के समक्ष रखा। सम्मेलन में क्रेडिंशियल कमेटी की रिपोर्ट कमेटी की अध्यक्षा सीमा चौहान ने रखी उनकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि सम्मेलन में कुल 114 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिनिधि पढ़ी-लिखी थी कोई भी इस सम्मेलन में निरक्षर प्रतिनिधि नहीं थी और दलित महिलाओं का हिस्सा ज्यादा था। सबसे बड़ी प्रतिनिधि हमीरपूर से ब्रहमी देवी जी थी जो 75 वर्ष की इस सम्मेलन में उपस्थित थी सबसे छोटी प्रतिनिधि सोलन जिला से प्रियंका थी वह 18 वर्ष की थी जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मापन भाषण:-

सम्मेलन के समापन भाषण में राष्ट्रीय महासचिव मरियम धवले ने भी कुछ प्रतिनिधियांे के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि हमारा संगठन एक राजनैतिक सोच रखने वाला संगठन है। हमारी राजनीति लोगों को उनका हक दिलाना है महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए संगठित करना है उन्होंने किसान आंदोलन को रेखांकित करते कहा कि जनवादी महिला समिति ने इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और हमने महिला को किसान का दर्जा देने की भी बात की। मनरेगा की मांग को उठाने के लिए उस पर महिलाओं को एकत्रित करने की जरूरत है बैठक में लिए गए निर्णयों को अमल में लाना होगा संगठन को नियोजित तरीके से चलाना है मुद्दों को पहचानना है उन्हंे उठाना है तथा उन मुद्दों के उपर संघर्ष चलाना जरूरी है। संगठन में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को पीछे छोड़ते हुए हम संगठन को आगे बढ़ाना है।

नई कमेटी का चयन:-

सम्मेलन में अगले तीन वर्ष के लिए 19 सदस्यीय कमेटी का भी चयन किया गया जिसमें स्थान खाली रखे गये और 8 सदस्यीय सचिव मण्डल का चयन किया गया। जिसमें अगले

तीन वर्षों के लिए अध्यक्ष पद पर डॉ0 रीना सिंह, राज्य सचिव फालमा चौहान तथा सोनिया शुब्रवाल को कोषाध्यक्ष चूना गया और संतोष कपूर, वीना वैद्य को उपाध्यक्ष तथा जयवंती, ममता नेगी तथा सीमा चौहान को सहसचिव चूना गया।

सम्मेलन के अंत में संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जो 1 जनवरी से केरल के त्रिवेद्रम में होने जा रहा है उसके लिए प्रस्ताव रखा गया जिसमें 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रस्ताव भी रखा गया तथा सम्मेलन के अंत में राज्य सहसचिव साथी जयवंती ने भी संगठनों के वालंन्टियरज का धन्यवाद किया तथा जिन लोगों ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिसने भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यख रूप से सहायता राशि दी थी या फिर कहीं से कोई भी खाना-पीना जिसके सौजन्य से था उनका भी जयवंती ने बहुत-बहुत धन्यवाद किया तथा राज्य अध्यक्ष डॉ0 रीना सिंह ने इसकी समाप्ति की घोषण की। अंत में 'हम होंगे कामयाब' के जोशीले गाने से सम्मेलन को अन्तिम रूप दिया।

गैर-बराबरी सभी के लिए घातक है

ज्ञान के सृजन एवं अर्जन के मार्ग में वर्ण-व्यवस्था बाधा बनकर खड़ी हो जाती है.
(30 अगस्त, 2022 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समीना दलवई के आलेख 'इनइक्वलिटी हर्ट्स अस आल' का हिंदी भावानुवाद)

अपने समुदाय के एक बालक के मृत शरीर को लेकर ब्राह्मण लोग भगवान् राम के दरबार में उपस्थित हुए. उन्होंने विलाप किया कि उनके राज में कहीं न कहीं अधर्म हो रहा था. शायद किसी शूद्र ने कोई तपस्या की हो. अन्यथा क्यों कोई ब्राह्मण बालक अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो सकता था? उन्होंने भगवान् राम से धर्म की रक्षा करने की विनती की. तलाश करते हुए राम एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक बालक संस्कृत के श्लोकों का जाप कर रहा था. राम ने उससे पूछा कि वह कौन था, और वह वहां क्या कर रहा था. बालक ने उत्तर देते हुए बताया कि उसका नाम शम्बूक था, वह एक आदिवासी था, तथा तपस्या कर रहा था. उसके तुरंत बाद राम के धनुष से निकले तीर ने शम्बूक के ह्रदय को बेध दिया. जैसे ही वह आदिवासी बालक धरती पर गिरा, वैसे ही उधर ब्राह्मण बालक जिन्दा हो उठा.

वाल्मीकि रामायण की यह कथा थोड़े थोड़े वर्षों के अंतराल पर सच साबित होती रहती है, जब कोई शूद्र, दलित अथवा आदिवासी छात्र शिक्षा ग्रहण करने का साहस करता है, तब उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है. ताजातरीन उदाहरण राजस्थान के नौ वर्ष के बालक इंद्र मेघवाल का है, जिसने अपने उच्च जाति के अध्यापक के लिए आरक्षित घड़े में से कथित तौर पर पानी पी लिया था.

बहुत सारे दलित छात्रों के लिए शिक्षा कोई स्वाभाविक रूप से आनंदमयी प्रक्रिया नहीं होती है. समूचे भारतवर्ष के स्कूलों में उनके उत्पीड़न तथा तिरस्कार की तमाम खबरें छपती रहती हैं. उनको अक्सर अन्य बच्चों से दूर बैठाया जाता है, अथवा उनको मिड-डे भोजन के लिए अलग से लाइन लगानी पड़ती है. कई जगहों पर वे पानी के सार्वजनिक नलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. उच्च शिक्षा भी ऐसे उत्पीड़नकारी घटनाक्रम से मुक्त नहीं है, जिसकी वजह से सेंथिल कुमार (2008), रोहित वेमुला (2016) तथा पायल तडवी (2019) जैसे दलित छात्र-छात्राओं को अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ता है.

देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं, जहां आज भी उसकी जाति उस व्यक्ति के व्यवसाय को निर्धारित करती है. उसका व्यवसाय उसकी बाध्यता होती है, न कि उसकी पसंद. वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लिखे हुए को पढ़ना जहां कुछ चुनिन्दा तबकों का विशेषाधिकार होता है, वहीं दूसरों को केवल शारीरिक श्रम करना होता है. यह विभेद ज्ञान के समग्र विकास के मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है. उदाहरण के लिए, मृत जानवरों की खाल खींचना तथा उस

खाल से चमड़े का निर्माण करना देश के बहुत से हिस्सों में आज भी निश्चित जातियों के लोगों का काम माना जाता है. उनका यह काम उनको उन पशुओं की शरीर रचना से परिचित कराता है. लेकिन उनको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही उपलब्ध नहीं है. इसलिए, मेडिकल साइंस का उनकी विशेषज्ञता से लाभान्वित होने का कोई चांस ही नहीं बनता है. दूसरी तरफ, ब्राह्मण तबका किसी मृत शरीर को छू तक नहीं सकता है. इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का यह पदानुक्रम समग्र औषधीय ज्ञान अर्जित करने में अड़चन पैदा करता है.

यह व्यवस्था आज भी काफी हद तक कायम है. जाहिर है कि इससे ज्ञान का सृजन बौना रह जाता है, तथा यह कल्पना-शीलता एवं नई खोज का गला घोंट देती है.

धर्म की अवधारणा अथवा जातिगत दायित्व के अनुसार निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों के लिए उपयोगी श्रम प्रदान करना होता है. इस उपयोगी श्रम का आर्थिक मूल्य उसकी सामाजिक जरूरत के स्थान पर श्रमिक की जातीय हैसियत से आंका जाता है. इसलिए, घरेलू काम काज से लेकर कचरा कर्मियों तक को लज्जाजनक पगार का भुगतान किया जाता है. कायदे से तो सफाई कर्मियों को, जो कि आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं, डॉक्टरों के समकक्ष वेतन मिलना चाहिए. लेकिन, न केवल उनको वेतन बहुत कम दिया जाता है, बल्कि उनके जोखिम भरे काम की भी अनदेखी की जाती है.

जातिगत भेदभाव हमारे प्रजातंत्र को बेचैन करने वाला है. जैसा कि अम्बेडकर ने कहा था कि आज़ादी के आन्दोलन ने हमें राजनैतिक लोकतंत्र तो उपलब्ध करा दिया है, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र अभी दूर की कौड़ी है.

(समीना दलवई जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत में प्रोफेसर हैं.)

एडवा उत्तराखण्ड राज्य का, 7वा राज्य सम्मेलन संपन्न

सुनीता पाण्डे
(केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

,'नफ़रत के खिलाफ हम सभी एक' के आह्वान के साथ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति उत्तराखण्ड का 7 वां राज्य सम्मेलन पार्क रोड़ स्थित कलावती धर्मशाला में 15 सदस्यीय राज्य कमेटी के चुनाव के साथ सम्पन्न हुआ।

सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महामंत्री मरियम धवले ने कहा कि केंद्र एवम राज्य की जनविरोधी नीतियों का असर मुख्य रूप से महिलाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने बिल्किस बानो केस का उदाहरण देते हुए कहा कि ये सरकारें दरअसल हर तबके की महिलाओं के खिलाफ है। आजादी के संघर्षों के बाद हिंदुस्तान के संविधान मै जितने अधिकार महिलाओं को मिले है उन सारे अधिकारों को ये सरकार धीरे धीरे छिन लेने की और अग्रसर है, उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं को आह्वान किया की वे अपने संघर्षशील इतिहास को याद करते हुऐ और मेहनती जिंदगी के दम पर संगठन को बनाने का काम करें और महिला एवम जन मुद्दों पर प्रभावी हस्तक्षेप करें। उदघाटन से पूर्व राज्य अध्यक्ष सुनीता पांडे ने झंडा फहराया और शहीद वेदी पर साथियो ने फूल चढ़ा कर श्रृद्धांजलि दी।

सम्मेलन को किसान सभा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पेंशन एसोसिएशन, डी वाय एफ आई, एस एफ आई , ए एल आई यू, बार काउंसिल उत्तराखंड की पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग , बी जी वी एस के साथियों ने शुभकामनाए दी, उदघाटन सत्र का समापन राज्य अध्यक्ष सुनीता पांडे ने किया।

सम्मेलन के आंतरिक सत्र में राज्य सचिव दमयंती नेगी ने विगत तीन साल की रिर्पोट सदन में रखी जिस पर 15 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया ।

सम्मेलन के दूसरे दिन राज्य महा मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों की चर्चा और सुझाओं का स्वागत कर रिर्पोट पर अपना जवाब दिया, तत्पश्चात रिर्पोट सर्व सम्मति से पास हुई।

सम्मेलन में 15 सदस्यों की राज्य कमेटी का गठन किया गया, जिसमें राज्य अध्यक्ष सुनीता पांडे, महामंत्री दमयंती नेगी, कोषाध्यक्ष चंदा ममगाई समेत, उपाध्यक्ष इंदु नौड़ियाल,, उप सचिव नुरेशा अंसारी नियुक्त हुई, तीन पद रिक्त रहे।

सम्मेलन में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी महिला हिंसा, बिल्किस केस के11आरोपियों की गुजरात सरकार द्वारा रिहाई और महिमामंडन के विरोध में, चमोली के हेलंग में महिला ओ के साथ अभद्रता, बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई सरकार एवं प्रशासन की भूमिका की निन्दा की गई ।सम्मेलन में राज्यभर में आपदा पीड़ितों की समस्याओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते सरकार से अविलम्ब पीड़ितों को समुचित सहायता देने ,राज्यभर में नशाखोरी की घटनाओं पर अविलम्ब अंकुश लगाने , महिला बिल को अविलंब पास कराने , बेतहाशा महगाई ,रसोई गैस तथा पेट्रो मूल्यबृध्दि तथा दैनिक इस्तेमाल की कीमतों में बृद्धि वापस लेने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत करने , आपदा एवम जंगली जानवरों के हमलो से हुए नुक्सान के मुआवाजे, एकल परित्यकता महिलाओं के योजनाओं आदि के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए।तत्पश्चात एडवा राज्य प्रभारी संध्या शैली ने सांगठनिक सत्र पर अपने संबोधन पर कहा कि पहाड़ की महिला कठिन परिस्थितियों में रहकर भी बड़े बड़े जन आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। वर्तमान मै आम जनता विशेषकर महिला वर्ग, दलितों, अल्पसंख्यकों पर केन्द्र सरकार के तीखे हमलो के विरोध में अपने जन तांत्रिक अधिकारों को हासिल करने के लिए बाधाओं को अवसर में बदलकर संगठन को मजबूत करते हुऐ संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरुरत है,

सम्मेलन मै देहारादून, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग जिले के लगभग 55प्रतिभागियों ने भाग लिया। आगामी 6से 9जनवरी 2023को केरल के तिवेंद्रम में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए 5प्रतिनिधियों को चुना गया। सभी प्रतिभागियों को राज्य उपाध्यक्ष इंदु नौडियाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।सम्मेलन का समापन राज्य अध्यक्ष सुनीता पाण्डेय ने किया ।

गंगा जमुनी तहज़ीब को बचाने तथा सद्भाव व एकजुटता बनाए रखने के लिए .. भाईचारा सम्मेलन

मधु गर्ग
(केंद्रीय कमेटी सदस्य, एडवा)

उप्र की राजधानी लखनऊ में दिनांक 30 अगस्त, 2022 को शहर के तमाम बुद्धिजीवी, संस्कृतिकर्मी, सामाजिक संगठनों, छात्रों, नौजवानों व सबसे बढ़कर एडवा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सद्भाव व एकजुटता के लिए गठित भाईचारा मंच के बैनर पर हुए सम्मेलन में हिस्सेदारी की। सैकड़ों की उपस्थिति से खचाखच भरे हॉल में वक्ताओं को जिस ध्यान से दर्शकों ने सुना, उससे स्पष्ट था कि ये मुद्दे उनके अपने जीवन से कितने गहरे तक जुड़े हुए हैं।

सम्मेलन के अध्यक्ष मंडल में वंदना मिश्रा, प्रो. रमेश दीक्षित, प्रेमनाथ राय, प्रो. नदीम हसनैन, प्रो. नलिन रंजन सिंह, प्रो. सूरज बहादुर थापा वह प्रो. विनोद चंद्रा शामिल थे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रो. रुपरेखा वर्मा ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि देश की आज़ादी अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा है। आज़ादी की इस विरासत को बचाते हुए लोकतंत्र व साझी विरासत को बचाये रखने के लिए सतत् अभियान चलाने होंगे।

सम्मेलन में जलेस के प्रांतीय सचिव प्रो. नलिन रंजन सिंह द्वारा प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में देश की गंगा जमुनी तहज़ीब को बचाने का संकल्प व सत्ता द्वारा जानबूझकर जनता की बुनियादी जरूरतों से ध्यान हटाने के लिए चलाई जा रही नफ़रत की मुहिम के खिलाफ संघर्ष का आह्वाहन किया गया। प्रस्ताव में भविष्य के लिए इस मुहिम को चलाने के लिए पदयात्राओं, पर्चा वितरण, नुक्कड़ सभाएं, गीत, नाटक आदि की योजना तथा महत्वपूर्ण तारीखों पर आयोजन करने के सुझाव भी थे।

प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रो. रमेश दीक्षित ने संविधान की मूलभूत भावना को बचाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि यदि इसे नहीं बचाया गया तो संविधान महज एक कागज की चिड़िया बन कर रह जायेगा। लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन है न कि बहुमत की तानाशाही होता है। संविधान अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी देता है तो वहीं वैज्ञानिक चेतना की वकालत

करता है, किन्तु आज इन सबके उलट बोलने, सोचने सबकी आजादी छीनी जा रही है। प्रो. रमेश ने कहा कि समाज के वंचित तबकों को ही लोकतंत्र व संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनके पास जाना और संगठित करना आज की बहुत बड़ी जरूरत है। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कुछ लाइनें कहीं "वो लोग जो कम निगाह जिनको समझ रहे हैं, नासमझ हैं, वही तो रौशनी कर रहे हैं"।

पश्चिम उत्तर प्रदेश भाईचारा सम्मेलन मंच के संयोजक व किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड डी पी सिंह ने देश में बढ़ते इस ख़तरे को दुनिया भर में साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा की जा रही लूट व ध्यान बंटाने के लिए जनता को जाति, धर्म व नस्ल के नाम पर बांटने के ख़तरे के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि आज मीडिया तांत्रिक की भूमिका में आ गया है, जो जनता के दिमागों पर कब्ज़ा कर रहा है। मीडिया का ही खेल है कि नोटबंदी में लाइनों में खड़े लोगों ने जान दे दी फिर भी वे मोदी का जयकारा बोल रहे हैं, रोजी रोटी छीनी जा रही है, सब कुछ बिक रहा है फिर भी मोदी का नाम जपा जा रहा है, हमें इस ख़तरे को समझना होगा। दरअसल अमृत महोत्सव में आज़ादी का जनाजा निकल रहा है। आज़ादी की लड़ाई में जिनका कोई योगदान नहीं था वही लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।

कामरेड डीपी सिंह ने आगे कहा कि देश की जनता के सामने एक बनावटी दुश्मन खड़ा कर दिया गया है और उसी के खिलाफ 80% जनता को जहरीला बनाया जा रहा है। राष्ट्र की अवधारणा ग़लत नहीं है किन्तु "राष्ट्रवाद " सांपों का बाड़ा है। जहां तक धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की बात है, वह केवल 10% अमीरों के हित में काम करते हैं। नेपाल और पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन ने सरकार को घुटनों पर ला दिया और उसके कुछ दिनों बाद ही देश का 29 करोड़ मज़दूर हड़ताल पर गया, किन्तु केंद्र में बैठी ख़तरनाक सांप्रदायिक विचारधारा की सरकार ने जनता का ध्यान किसान व मजदूरों के मुद्दों से हटाने के लिए रामनवमी, हनुमान जयंती, लाउडस्पीकरों की ऐसी नफ़रती राजनीति की कि पूरे देश में जगह जगह सांप्रदायिक तनाव व दंगे होने लगे। इनका यही खेल जनता को बताने की ज़रूरत है। आम जनता दंगा नहीं चाहती है। पेट के सवाल पर जनता को लामबंद करना होगा नहीं तो 2024 में तालिबान की वापसी हिंदुस्तान में होगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. सूरज बहादुर थापा ने आने वाले समय के लिए एक रोड मैप बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं को संगठित कर उनकी समझ को साफ करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रोफेसर विनोद चंद्रा ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति द्वारा उच्च शिक्षा को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने भारत की बहुलतावादी संस्कृति को इसकी खूबसूरती बताते हुए कहा कि एक विचार और एक संस्कृति हो ही नहीं सकती। मध्यमवर्गीय लोगों द्वारा मौन की संस्कृति बहुत ख़तरनाक है।

एडवा की मधु गर्ग ने कहा कि उनका संगठन लगातार लोगों और विशेषकर ग़रीब बस्तियों में लोगों के बीच जाकर सद्भावना वह मोहब्बत का संदेश दे रहा है। महिलाएं भूख, ग़रीबी, मंहगाई से बेहाल हैं, किन्तु उन्हें धर्म और जाति के खांचों में बांटा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय भय के साये में जी रहा है, उनके छोटे छोटे काम धंधे बंद हो रहे हैं, क्योंकि अब हिंदू ग्राहकों को उनसे सामान खरीदने की मनाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता केवल अल्पसंख्यक समुदायों को ही निशाना नहीं बनाती बल्कि देश के नागरिकों पर भी हमला करती है। संविधान ने "हम भारत के लोग" कहा, किन्तु ये नफ़रती सत्ता देश के नागरिकों को प्रजा बनाना चाहती है। बिल्कीस बानो का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले ने स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग संविधान की जगह मनुस्मृति लाना चाहते हैं, तभी तो बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा जा रहा है। हाथरस केस में दलित लड़की के ठाकुर बलात्कारियों को बचाने के लिए पूरी व्यवस्था ने जड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इनका न्यू इंडिया है जिसमें एक मासूम दलित की पानी छूने पर हत्या कर दी जाती है। सभी जनसंगठनों व जनवादी ताकतों को एक होकर इनका मुकाबला करना होगा । हमारे पास हमारी समृद्ध व साझी विरासत है जिसे लेकर लोगों के पास जाना होगा।
एन.ए.पी.एम. की अरुंधती धूरु ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की तुलना गांधी जी के तीन बंदरों से की जो देख सुन व बोल नहीं सकतीं। मंचारी नेता एन के सिंह ने कहा कि आज हमें लड़ने से भी रोका जा रहा है। सीटू से राहुल मिश्रा ने दवा कंपनियों की लूट पर अपनी बात रखी। इप्टा के राकेश जी ने कहा कि किसानों से आंदोलन करने का तरीका सीखना होगा।

सम्मेलन के समापन भाषण में प्रो. नदीम हसनैन ने हबीब तालिब की नज़्म की कुछ पंक्तियों से अपनी बात रखी :-

"इस खुले झूठ को, जेहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता" .

सम्मेलन के अंत में इप्टा द्वारा प्रेमचंद की कहानी "मंदिर" पर आधारित एक लघु नाटिका का भी मंचन हुआ। अति उत्साह व दृढ़ संकल्प के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ।

आगे भी कारंवा चलता रहेगा ..